



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 675]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1999/कार्तिक 22, 1921

No. 675]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1999/KARTIKA 22, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1999

का.आ. 1089(अ).—साधारणतया पी०एल०ए० के रूप में ज्ञात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट {आर०पी०एफ०}, दी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट {यू०एन०एल०एफ०}, दी पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक {पी०आर०ई०पी०ए०के०} और उसके सशस्त्र खण्ड "रेल आर्मी" कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी {के०सी०पी०} और इसके सशस्त्र विंग जिसको भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली याओल कानबा लुप {के०वाई०के०एल०} तथा मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट {एम०पी०एल०एफ०} जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से मैती उग्रवादी संगठन कहा गया है। ने:-

{I} मणिपुर राज्य को भारत से अलग कर स्वतंत्र मणिपुर के गठन का अपना उद्देश्य खुले तौर पर घोषित कर दिया है,

{II} अपने उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र साधन रखे हैं और उनका उपयोग करता है,

॥११॥ मणिपुर में सुरक्षा बलों, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों और कानून का पालन करने वाले नागरिकों पर आक्रमण करते रहे हैं,

॥११॥ अपने संगठन के लिए धन संग्रहण हेतु असैनिक आबादी को अभिप्रास, उद्यापन और दूतने की गतिविधियों में लिप्त है, और

॥१॥ लोकमत को प्रभावित करने और अपने अलगाववादी उद्देश्य की अभिप्राप्ति के प्रयोजनार्थ शस्त्र और प्रशिक्षण की सहायता प्राप्त करने हेतु विदेशी स्त्रोतों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं ।

2. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पूर्वोक्त कारणों से मैती उग्रवादी संगठन और उनके द्वारा बनाए गए अन्य निकाएं जिनमें ऊपर नामित सशस्त्र समूह भी है, विधि विरुद्ध संगम हैं ।

3. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 ॥1967 का 37॥ की धारा 3 की उपधारा ॥1॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् दी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो सामान्यतः पी०एल०ए० के नाम से जानी जाती है और उसके राजनीतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट ॥आर०पी०एफ०॥, दी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट ॥यू०एन०एल०एफ०॥, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक ॥पी०आर०ई०पी०ए०के०॥ और इसका सशस्त्र विंग "रेड आर्मी" कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी ॥के०सी०पी०॥ और उसके सशस्त्र खण्ड जिसको भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगलीपाक कानबा लुप ॥के०वाई०के०एल०॥ तथा मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट ॥एम०पी०एल०एफ०॥ को गैर कानूनी संगम घोषित करती है ।

4. और:

॥१॥ सुरक्षा बलों और असैनिक आबादी पर ॥सशस्त्र समूहों और मैती उग्रवादी संगठनों के सदस्यों॥ द्वारा आक्रमण और हिंसा के मामले बार बार हुए हैं तथा हो रहे हैं,

॥१॥ मैती उग्रवादी संगठनों की संख्या में वृद्धि हुई है,

§ 111/1 निरन्तर धन संग्रहण, उद्यापन और परिष्कृत हथियार अर्जित किए जा रहे हैं,

§ 111/1 शरण लेने, प्रशिक्षण लेने तथा हथियार और गोलाबारूद छिपाकर प्राप्त करने के लिए कुछ पड़ोसी देशों में कैम्प बनाए हुए हैं ।

5. केन्द्रीय सरकार की राय है कि मैती उग्रवादी संगठन के पूर्वोक्त क्रियाकलाप, भारत की प्रभुता एवं अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यदि उनपर तुरन्त रोक न लगाई जाए और उन्हें नियंत्रित न किया जाए तो उक्त मैती उग्रवादी संगठन पुनः समूहबद्ध होंगे, अपने को हथियारों से सुसज्जित करेंगे, अपने काइरों का विस्तार करेंगे, परिष्कृत हथियार प्राप्त करेंगे, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों एवं सिविलियनों की हत्या करेंगे और भारत से मणिपुर को अलग करने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने क्रियाकलाप की गति तीव्र करेंगे ।

6. अतः, अब उपर्युक्त पैरा 4 और पैरा 5 में निर्दिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह आवश्यक है कि मैती उग्रवादी संगठनों अर्थात् पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो सामान्यतः पी०एल०ए० के नाम से जानी जाती है और इसके राजनैतिक खण्ड दी रिवॉल्यूशनरी पीपुल्स फ्रन्ट § आर०पी०एफ० § दि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट § यू०एन०एल०एफ० §, पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक § प्रीफाक §, तथा इसका सशस्त्र विंग "रेड आर्मी" कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी § के०सी०पी० § और उनके सशस्त्र खण्ड जिसे भी "रेड आर्मी" कहा जाता है, कांगली या ओल कानबा लुप § के०वाई०के०एल० § तथा मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रन्ट § एम०पी०एल०एफ० § को तत्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाए और तदनुसार उक्त धारा 3 की उपधारा § 3 § के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जाने वाले किसी आदेश के अध्याधीन, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th November, 1999

S.O. 1089(E).—Whereas the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF) (hereinafter collectively referred to as the Meitei Extremist Organisations) have:

- (i) openly declared as their objective the formation of an independent Manipur by secession of Manipur State from India;
- (ii) been employing and engaging in armed means to achieve their aforesaid objective;
- (iii) been attacking the Security Forces, the Police, Government employees and law-abiding citizens in Manipur;
- (iv) been indulging in acts of intimidation, extortion and looting of civilian population for collection of funds for their organisation; and
- (v) been making efforts to establish contacts with sources abroad for influencing public opinion and for securing their assistance by way of arms and training for the purpose of achieving their secessionist objective.

2. And whereas, the Central Government is of the opinion that for the reasons aforesaid, the Meitei Extremist Organisations and other bodies set up by them, including the armed groups named above, are unlawful associations.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Meitei Extremist Organisations, namely, the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur

People's Liberation Front (MPLF) to be unlawful associations.

4. And whereas,--

- (i) there have been repeated continuing and ongoing acts of violence and attacks by (armed groups and members of the Meitei Extremist Organisations) on the Security Forces and the civilian population;
- (ii) there has been an increase in the strength of the Meitei Extremist Organisations;
- (iii) there has been continued collection of funds/extortions and acquisition of sophisticated weapons;
- (iv) camps in some neighbouring countries continue to be maintained for the purpose of sanctuary, training and clandestine procurement of arms and ammunition.

5. And whereas, the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the Meitei Extremist Organisations are detrimental to the sovereignty and integrity of India, and if these are not immediately curbed and controlled the said Meitei Extremist Organisations would regroup and rearm themselves, expand their cadres, procure sophisticated weapons, cause heavy loss of lives of civilians and Security Forces, and accelerate their activities aimed at secession of Manipur from India.

6. Now, therefore, having regard to the circumstances referred in paragraph 4 and 5, the Central Government is of the opinion that it is necessary to declare the Meitei Extremist Organisations, namely, the People's Liberation Army, generally known as the PLA, and its political wing the Revolutionary People's Front (RPF), the United National Liberation Front (UNLF), the People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) and its armed wing the "Red Army", the Kangleipak Communist Party (KCP) and its armed wing also called the "Red Army", the Kanglei Yaol Kanba Lup (KYKL) and the Manipur People's Liberation Front (MPLF), as unlawful associations with immediate effect; and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of the said section (3), the Central Government hereby directs that the Notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of publication in the Official Gazette.

[File No.-8/16/99-NE.-I]

